



संपादकीय

## कोर्ट की मोहर

आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने साल 2016 में हुई नोटबंदी पर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक तथा याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी थीं। जस्टिस एस. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीट ने नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया। जबकि न्यायमूर्ति बी.वी. नागरल्ला ने फैसले से असहमति जतायी। दरअसल, इन याचिकाकर्ताओं ने नोटबंदी के विभिन्न पक्षों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायाधीशों का मानना था कि आरबीआई कानून की धारा 26(2) की शक्तियों के आधार पर बैंक नोट की किसी भी सीरीज को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने 'किसी भी' सीरीज को सभी सीरीज को प्रतिबंधित करने के अधिकार के रूप में नहीं देखा। वहीं अदालत का कहना था 'किसी भी' शब्द को तंग नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी कि केंद्र सरकार व केंद्रीय बैंक को आर्थिक नीतियों की सुरक्षा हेतु सेंट्रल बोर्ड के साथ विमर्श करने की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर फैसले से असहमत जस्टिस बी.वी. नागरल्ला का कहना था कि केंद्र द्वारा सभी सीरीज के नोट को प्रचलन से बाहर करना गंभीर विषय था। साथ ही यह कि केंद्र को यह फैसला अधिसूचना के बजाय विधेयक के जरिये लेना चाहिए था। विषय के महत्व को देखते हुए संसद के समने रखना चाहिए। यह भी कि आरबीआई ने फैसला केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिया था। दूसरी ओर न्यायमूर्ति गवर्नर ने नोटबंदी के उद्देश्यों को तार्किक बताया। उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने आठ नवंबर, 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इस निर्णय के बाद कई सप्ताह तक बैंकों व एटीएम में पुराने नोट बदलवाने के लिये लंबी लाइनें देखी गईं। कई जगह अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। वहीं कोर्ट ने मामले को अकादमिक बताये जाने और निर्णय को लेकर लंबा अर्सा बीतने पर सवाल उठाये थे। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील पी. चिंदंबरम का कहना था कि ऐसे निर्णय में अनुशंसा केंद्रीय बैंक की तरफ से आई चाहिए थी। उन्होंने विगत में नोटबंदी को लेकर संसद में कानून पारित करने के फैसले का हवाला दिया। उनकी दलील थी कि केंद्र ने कोर्ट के समक्ष पर्याप्त दस्तावेज नहीं रखे। सवाल उठाया कि क्या यह फैसला लेने के बाद केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बोर्ड की बैठक के सभी नियमों की पालन हुई? वहीं आरबीआई के वकील का कथन था कि फैसले की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और बैंक ने फैसले की संस्तुति की थी। साथ ही सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सभी जरूरी शर्तों का पालन हुआ था। दूसरी ओर याचिकाकर्ता आरबीआई कानून की धारा में शामिल शब्द 'किसी भी' की नये सिरे से व्याख्या करने की मांग करते रहे। वहीं बैंक के वकील इससे असमंजस की व्यापक आर्थिक नीति का एक भाग था, जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय बैंक के साथ समझस्य से ही संभव था। दरअसल, सरकार का दावा था कि नोटबंदी एक सुविचारित फैसला था और इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ता उस दलील को नहीं मानते कि सकल घेरेतु उत्पाद और चलन में आई मुद्रा के अनुपात असंतुलन को दूर करने के लिये यह कदम उठाया गया था। उनका तर्क है कि मौजूदा अनुपात नोटबंदी के समय से ज्यादा असंतुलित है। सवाल अर्थव्यवस्था से जाली नोट को बाहर करने के लक्ष्य की सार्थकता को लेकर भी उठे।

आज का राशीफल

<b>मेष</b>	संतान के दधित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिशत में वृद्धि होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलापा पूरी होगी। वाणी की साम्यता बनाये रखने की आवश्यकता है।
<b>वृषभ</b>	परिवारिक जीवन सुखयोग होगा। उपहार व सम्पान का लाभ मिलेगा। यात्रा में अपने सामन के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आंखें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन हानि की संभावना है।
<b>मिथुन</b>	जीवनसाथी का सहयोग व सनिधि मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपका लाभ मिलेगा। प्रम प्रसंग प्रगति होगी। भारी व्यय का सामन करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
<b>कर्क</b>	व्यावसायिक व परिवारिक योजना सफल होगी। संतान के दधित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें। नए अनुबंध प्राप्त होंगे।
<b>सिंह</b>	व्यावसायिक योजना सफल होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवारिक जीवन का सहयोग मिलेगा। वाद विवाद की स्थिति आपके दिमां में न होंगी। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयोग सफल होगा।
<b>कन्या</b>	वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परिवारिक जीवनों के मध्य सुखद समय उत्जरोग। वाणी की सौभायता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दधित्व की पूर्ति होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
<b>तुला</b>	आर्थिक योजना को बल मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी से तनाव मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्पान का लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। धन लाभ की ओर रहें।
<b>वृषभिक</b>	जीवनसाथी का सहयोग व सनिधि मिलेगा। धन, पद, प्रतिशत में वृद्धि होगी। एप्पे ऐसे के लेने देने में सावधानी रखें। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलापा पूरी होगी। यात्रा देशांतर की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
<b>धनु</b>	आर्थिक दिशा में प्रगति होगी। परिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। व्यर्थ की भागीदारी होगी।
<b>मकर</b>	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। यजैतीक श्वेत्र में किए गए प्रपात सफल होंगे। वाणी की सौभायता आपको लाभ दिलायेगी। भारी व्यय का सामन करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
<b>कुम्भ</b>	परिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दधित्व की पूर्ति होगी। खान-पान में संयंत्र रखें। इस दिशा में प्रगति होगी। विरोधी परास्त होंगे। समुखल पक्ष से लाभ होगा।
<b>मीन</b>	जीवनसाथी का सहयोग व सनिधि मिलेगा। शिशा प्रतिवेशिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। मित्रों या रिसेप्शन से पोंगी मिलेगी। नेत्र विकार की संभावना है। एक दो तीन दिनों तक हो सकती है।

विचार मंथन

भारत में लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों तक पहुंचने और समावेश का 70 वर्षीय इतिहास रहा है। चुनाव आयोग ने लाखों आंतरिक प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग या दूर से ही मतदान करने देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, उनमें से लगभग 85 प्रतिशत लोग रोजगार, शिक्षा, विवाह या परिवार के स्थानांतरण के चलते अपने ही राज्य में गांवों से शहरों की ओर रहने चले जाते हैं। ऐसे में, चुनाव आयोग का यह फैसला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग की मांग पूरी करेगा। मल्टी-कंस्टीट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) वर्षों की मेहनत से तैयार की गई है, जो अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को मतदान में सक्षम बनाएगी। यह चुनाव आयोग के मुताबिक, प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का

# नववर्ष 2023 में दिल्ली वासियों को जाम से निजात



(लेखक - विनोद तकियावाला)

काल का चक्र महाकाल के ईशारे पर निरंतर-निर्विधन घुम रहा है। तभी तो किसी दार्शनिक ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का अपरिहार्य व सांख्यनिक नियम है इससे हम सभी भली भाँति परिवर्तित हैं। जिसका आरम्भ हुआ है उसका अंत निश्चित है। जिसका आगमन हुआ उसका जाना निश्चित है कुछ ऐसा ही सन 2022 का अंत हो रहा है वर्ष 2023 का आगमन का आगाज हो गया है जाने वाले सन 2022 को अलविदानव वर्ष सन 2023 का स्वागत करने हम सभी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सभी अपने चिर परिवर्तिबन्ध-वान्धवों-मित्र परिजन को नव की शुभ कामनाएं व उपहार भेट करने में व्यस्त हैं तो कुछ नये साल की संकल्प कार्य योजना को लेकर व्यस्त है। इसी क्रम में केन्द्र सरकार/दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए कई राष्ट्रीय राजधानी से नव निर्माणाधीन परियोजना को तैयार करने दिन रात मेहनत कर रही है। इन परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन अंडर पास एक प्लाई ओवर अनवरत कार्य कर रही है इसका का लाभ फरवरी तक मिलने लगेगा। इसमें किंवद्दन नगर अंडर पास तैयार है। आप को बता दे कि नया साल दिल्ली वासियों को जाम से निजात मिलेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की चार बड़ी परियोजनाएं अगले दो माह में पूरी होने जा रही हैं। इसमें एक अंडरपास का उद्घाटन जनवरी के पहले सप्ताह में ही हो सकता है तीन अन्य परियोजनाएं भी फरवरी के अंधिकार तक जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। इससे रिंग रोड पर दक्षिणी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक के लोगों को यातायात जाम से राहत मिलेगी। शाथ ही शाथ महिला सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी सुरक्षित है। पहली तिमाही में एक लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे और लगा दिए जाएंगे। गांधी विहार में वजीराबाद और जगतपुर के बीच मेट्रो की परियोजना को दो आधे अंडरपास के साथ अनुमोदित किया गया था। जो अभी भी बाहरी रिंग रोड पर बुराड़ी और वजीराबाद के बीच निर्माणाधीन हैं। सर्व विदित रहे कि यह सड़क शहर की सबसे व्यस्त और चौड़ी सड़कों में से एक है। इस कारण हमेशा इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वही गांधी विहार अंडरपास के पैदल यात्रियों वाले भाग को तैयार कर लोगों द्वारा इसका उपयोग शुरू करने के बाद काफी राहत मिली है। इस क्षेत्र

में कई कोचिंग संस्थान भी हैं। निर्माणधीन इसअंडरपास के जिस भाग से वाहन गुजरने हैं इसे जनवरी तक तैयार किए जाने का लोक निर्माण विभाग का लक्ष्य है। वही जगतपुर अंडरपास के निर्माण पर 38 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित बजट में भले ही नहीं बढ़ा है लेकिन परियोजना दो साल देरी से पूरी हो रही है। ऐरों मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए ऐरों मार्ग रिंग रोड टी-प्लाईट पर अंडरपास बनाया जा रहा है इससे मथुरा रोड से आकर ऐरों मार्ग होते हुए सीधे रिंग रोड पर जा सकेंगे। इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अभी ऐरों मार्ग से रिंग रोड पर आश्रम की ओर जाने के लिए पहले एक किलोमीटर के करीब आइटीओ की ओर जाना होता है। उसके बाद पेट्रोल पंप के पास से यू-टर्न लेकर वापस आना होता है। ऐसे में यू-टर्न लेने वाले वाहनों की वजह से इस प्लाईट पर भी जाम लग रहा है इसे सिंतंबर तक तैयार हो जाना आश्रम रेलवे लाइन के नीचे काम में आ रही जटिलता के चलते अब यह कार्य जनवरी या फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है परियोजना का कार्य पूरा डेढ़ साल पीछे चल रहा है यह अंडरपास वैसे तो सुरंग सड़क परियोजना का हिस्सा है इसकी राशि उसी आठ सौ करोड़ में समिलित है लेकिन अंडरपास की कुल राशि 80 करोड़ रुपये मानी जा रही है इन दिनों आश्रम और उसके आस-पास के इलाके को जामकुर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा स्ट्रेच जामकुर हो जाएगा। यहां चल रहा आश्रम पलाईओवर का विस्तार कार्य जनवरी से लेकर फरवरी तक पूरा हो जाएगा इसके बनने से आश्रम चौक और डीएनडी तथा आश्रम चौक से सराय काले खां की ओर आना जाना आसान हो जाएगा। इस परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पलाईओवर विस्तार का निर्माण कार्य जून 2020 में शुरू हुआ था इस परियोजना की कुल लागत 128.25 करोड़ रुपये है। पलाईओवर की कुल लंबाई 1425 मीटर है। इसे सिंतंबर 2022 में पूरा किया जाना था बनकर तैयार है। इसी तरह आइएनए में पूर्वी किंदवई नगर और दिल्ली हाट बाजार के बीच पैदल यात्रियों के लिए बने अंडरपास पर लोक निर्माण विभाग ने काम लगभग पूरा कर लिया है। अधिकारियों के मूर्तविक इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगाजिससे नए साल में साल में लोगों को इसकी भी सुविधा मिल सकेगी। बहु परिक्षित इस परियोजना का शुरुआती समय सीमा इस साल मई थी और पहली समय सीमा अगस्त 2021 थी लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना में लाकडाउन के कारण पूरे शहर में काम टप होने के कारण परियोजना में विलंब हुआमगर 50 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब पूरी हो गई है। यहां लिपट और एस्केलेटर भी लगाए जाने की योजना है। विश्वनीय सुत्रो ने बताया कि तीन अंडरपास और एक फ्लाईओवर का लाभ फरवरी तक मिलने लगेगा। इसमें किंदवई नगर अंडर पास तैयार है। इसे जनवरी में खोल दिया जाएगा। अन्य परियोजनाओं को भी जनवरी में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है अब हम केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित परियोजना की चर्चा करते हैं। हरियाणा के सोहना से राजस्थान तक 276 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे का काम अंतिम चरण में है। आठ लेन के इस एक्सप्रेस-वे को फरवरी 2023 में शुरू कर दिया जाएगा जिसे ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है। दिल्ली के आश्रम अंडरपास के पास से दिल्ली- मुंबई कनेक्टर बनाया जाएगाजिसके मार्च 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली- चंडीगढ़ दिल्ली- द्वारका दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस-वे व आई जी आई एयर पोर्ट को जोड़ने के लिए 75.5 किलोमीटर लंबे अर्बन एक्सटेंशन रोड का निर्माण कार्य जोरों पर है और अगस्त 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड बनने से वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल सकेंगे। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से गीता कालोनी और यूपी बार्डर के रास्ते लोनी और बागपत होते हुए दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 210 किलोमीटर होगी। 16लेन का यह एक सप्रेसवे सीधे आई टी ओ सिनेचर बिजआई एस वी टी कश्मीरी गेट और दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा और इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा होने की सम्भावना है। एक पलाईओवर जो डीएनडीआश्रम एम्स की ओर आने-जाने वाले वाहनों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए निर्माण किया जा रहा है। बहु इस परियोजना का शुरुआती समय सीमा इस साल मई थी और पहली समय सीमा अगस्त 2023 में लिए खोल दिया जाएगा।

# कौशल विकास हो प्राथमिकता

**कौशल विकास हो प्राथमिकता/ दिनेश भारद्वाज**

राजनीतिक दल यह अच्छे से समझ चुके हैं कि 'युवा' हो रहे देश में युवाओं के साथ के बिना सत्ता मुश्किल है। तभी तो हरियाणा सहित छह राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने युवाओं को लुभाने, रिझाने और मनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की है। यह बात अलग है कि अभी तक पूरी तरह किसी भी राज्य के युवाओं को यह अधिकार नहीं मिला है। हरियाणा के बाद अब झारखण्ड सरकार भी अगले साल जनवरी से प्राइवेट सेक्टर की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व करने जा रही हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए खास थे। भाजपा सत्ता में थी और मनोहर लाल के नेतृत्व में '75 प्लस' के नारे के साथ चुनाव लड़ा गया। पांच साल की एंटी-इन्कमबोर्सी भी थी और भी दूसरे राजनीतिक कारण थे कि भाजपा चालीस का आंकड़ा मुश्किल से छू पाई। इनेलो से अलग होकर अस्तित्व में आई दुष्प्रथं चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने इन चुनावों में ऐसा प्रदर्शन किया कि सत्ता की 'चाबी' उसके हाथों में आ गई। जजपा को 10 सीटों पर विधायक मिले। नब्बे हलकों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा को दूसरी बार सत्तासीन होने के लिए छह विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में उसे 10 विधायकों वाली जजपा का साथ मिला। जब दो दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो लाजिमी है कि चुनावी मुद्दों पर भी सौदेबाजी हुई होगी। गठबंधन की सरकार में डिटी सीएम बने दुष्प्रथं सिंह चौटाला प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मूल निवासी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का अपनी पार्टी का चुनावी वादा पूरा करवाने में कामयाब रहे। हरियाणा विधानसभा ने 2020 में 'हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020' करने के लिए विधेयक पारित किया। इसमें अड़चनें भी आई, लेकिन दूर कर ली गई। पहले 50 हजार तक वेतन वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया था। स्थानीय कंपनियों व उद्यमियों की मांग और नाराजगी के बीच 50 की बजाय 30 हजार तक वेतन की नौकरियों में इस कानून को लागू करने की सहमति बनी। 15 जनवरी, 2021 से इसे राज्य में

लागू करने का नाटापकशन भी जारी हो गया। फरीदबाद इंडस्ट्रियल एसेसिंशन व अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को नुनौती दी। ललील दी गई कि प्राइवेट सेक्टर में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों का चयन होता है। अगर सरकार के दबाव में नोकरियां दी गईं तो वे अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट छारा लगाए गए स्टे को हटा दिया। हालांकि अंतिम फैसला हाईकोर्ट पर ही छोड़ दिया। इस बीच, रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति सरकार को दे दी। बहरहाल, मामला हाईकोर्ट में ही लंबित है और प्रदेश के युवाओं को इंतजार है कि कब 75 प्रतिशत आरक्षण के तहत उन्हें स्थानीय कंपनियों व उद्योगों में रोजगार मिलेंगे। प्रदेश की उन सभी प्राइवेट कंपनियों, उद्योगों द्रस्ट आदि में यह फैसला लागू होना है, जहां स्टॉफ की संख्या 10 से अधिक है। बेशक, इस तरह के कानून सविधान की मूल भावना के खिलाफ ही माने जा रहे हैं। चूंकि सविधान में सभी की बाबरी का हक दिया हुआ है। हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इस तरह के कानून बने हुए हैं। बिंदबाना यह है कि इन राज्यों में या तो यह कानून सही से लागू नहीं हो पाया है या फिर कोर्ट-कवरही के बजाए लटका हुआ है। बेशक, हरियाणा ने कोशिश की है कि कंपनियों पर फैसला थोपने की बजाय प्रदेश के युवाओं को इस योग्यता बनाया जाए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग उन्हें राजी-राजी अपनायाँ रखें। इसके तहत युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत ट्रेनिंग भी देने की व्यवस्था शुरू की गई। मार्केट में डिमांड के हिसाब से युवाओं को तैयार किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वे मार न खाएं। हरियाणा के लेकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों के अनभव बहत अच्छे नहीं हैं।



पूर्व में गुरुग्राम मारुति 10 और होंडा सहित कई कंपनियों में बढ़े विवाद हो चुके हैं। श्रमिकों के आंदोलन की वजह से कई दिन काम प्रभावित रहे हैं। शायद, ये विवाद भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का कारण हो सकते हैं। आमतौर पर किसी भी राज्य के उद्योगपति और कंपनियों के मालिक स्थानीय युवाओं की बजाय दूसरे राज्यों के लोगों को नैकरियों में तबज्जो देते हैं। स्थानीय होने के बलते यूनियन भी जल्दी बनती हैं और प्रभावी भी रहती हैं। बहरहाल, हरियाणा की गठबंधन सरकार का यह 'सप्ना' अभी अधूरा है। झारखण्ड की सरकार भी नये साल से इसे अपने यहां लागू तो करने जा रही है, लेकिन कितनी कामयाब होगी, इस पर संशय ही बना रहेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी। बाल टाकरे के समय उठी मराठी मानुष की आवाज कारगर रही। हालांकि यह फैसला दूसरे राज्यों में नाराजगी का कारण भी बना। धीरे-धीरे कई राज्य इसी दिशा में आगे बढ़े। जरूरत इस बात की है कि सरकार इस तरह के कानून बनाने की बजाय युवाओं को इस तरीके से तैयार करे कि प्राइवेट कंपनियों के पास उन्हें न चुनने के लिए कोई विकल्प ही न बचे।

# रिमोट वोटिंग से मजबूत ही होगा हमारा लोकतंत्र

संशोधित संस्करण है। किसी भी चुनाव से पहले, एक दूरस्थ मतदाता को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को सूचित करना पड़ेगा। मतदाता का सत्यापन के बाद दूर रहते हुए भी मतदान की सुविधा हासिल हो जाएगी। ऐसे मतदाता दूरस्थ बहु-निर्वाचन मतदान केंद्र पर आरवीएम का उपयोग कर मतदान का सकेंगे। रिमोट मतदाता बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद का प्रयोग करेंगे और मतदान रिमोट कंट्रोल यूनिट में राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार संख्या के साथ दर्ज हो जाएगा। हालांकि, सुधार की यह राह लंबी होगी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव संचालन नियमों और निर्वाचकों के पंजीकरण नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे। एक प्रवासी मतदाता, मतलब बाहर रहने वाले मतदाता का परिभाषित करना पड़ेगा। सामान्य निवास और अस्थायी

निवास जैसी अवधारणाओं को ठीक से समझना होगा। इसी तरह, रिमोट वॉटिंग के लिए एक स्पष्ट कानून परिभाषा और स्पष्टीकरण की जरूरत होगी कि एनिवार्चन क्षेत्र, जिले या राज्य के बाहर कौन से स्थान इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा, बाहर रखे गये वालों के आंकड़े और उनकी परिभाषा अस्पष्ट है, जबकि चुनावी पंजीकरण प्रादेशिक है और सामान्य निवास का आधारित है। दूरदराज के मतदाताओं की सूची बनाविधित विशेष मतदान केंद्रों की स्थापना, दूरदराज मतदाताओं की पहचान, विशेष कर्मचारियों की तैनाती और इन स्थानों पर आर्टर्श आचार सहित को लागू करने के लिए विस्तृत तैयारी की जरूरत पड़ेगी। रिमोट वॉटिंग मतदान में सुधार करने में मदद कर सकती है, परन्तु मतदाता भागीदारी के मुद्दे को हल नहीं करती है। शाही

नागरिकों की मतदान के प्रति उदासीनता और युवा वर्ष अरुचि ने चुनाव-दर-चुनाव कड़वाहट पैदा कर दी और इसके लिए अलग व अधिक अनुकूल समाधानों जरूरत पड़ी। भारत के आंतरिक प्रवासियों का करोड़ का मजबूत समूह मतदान बढ़ाने में मदद सकता है। पिछले दो आम चुनावों (2014 और 2019 में) क्रमशः 66.4 प्रतिशत और 67.4 प्रतिशत मत हुआ है, जो उसके पहले के लोकसभा चुनाव में प्रतिशत की तुलना में नाटकीय वृद्धि थी। 30 करोड़ भारतीय मतदाताओं के बारे में प्रश्न और चिंता ने एक दशक पूर्व एक जागृति पैदा की थी, जब चुनाव आयोग भी चुनाव आयोगीदारी बढ़ाने को अपने एजेंडे के केंद्र में ले आया तब से चिरर्यों का मतदान बढ़ रहा है, जिसने कई राज्यों में पुरुषों को पिछे छोड़ दिया है। रिमोट वोटिंग में भी

ही गति बनाए रखने की जरूरत है। चुनाव प्रबंधकों के लिए कीवर्ड गोपनीयता, वोट की सुरक्षा और पारदर्शिता, तीन अवधारणाएं हैं, जो आरवीएम के इस्तेमाल में खास होंगी। ईवीएम को स्वीकार करने में ही हमें कई चरणों का समय लगा है और अब भी हारे हुए उम्मीदवार इस पर संदेह जाता ही देते हैं, तो आरवीएम को भी आलोचना व संघर्ष से गुजरना होगा। 2023 में नौ राज्यों के चुनाव तय हैं। यह आरवीएम के परीक्षण का सही मौका है। उम्मीद है, 16 जनवरी को राजनीतिक दल राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि अपने मतदान क्षेत्र से दूर कहीं फंसे या मजबूर ऐसे मतदाताओं के बारे में सोचें, जो मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी व अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलना ही चाहिए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)





# डेरारा हुरिसा 2023 टाटा मुंबई मैराथन में अपने ताज का बचाव करेंगे

(एंजेसी)

इथोपिया के डेरारा हुरिसा 15 जनवरी, 2023 को मुंबई में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे प्रतिक्रिया-टाटा मुंबई मैराथन में अपने खिलाफ की रक्षा करने के लिए कुछ बेहतरीन एलाइट पुरुष धावकों के साथ प्रतिष्पत्ति करेंगे। इस रेस में दिस्ता लेने वाले पुरुषों में उन्हें भर का व्यक्तिगत श्रेष्ठ समय 2020 में काम 2:08:09 घंटे के कोर्स रिकार्ड से बहरत है। 405,000 अमेरिकी डालर इनमी राश वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रोड रेस का 18वां संस्करण महामारी के कारण दो साल के ब्रेक

के बाद आयोजित हो रहा है। इसकी बुधप्रतीक्षित वापसी पर छह श्रेणियों में 55,000 से अधिक एम-प्रायर धावक भी मुंबई की सड़कों पर दौड़ें दिखाएं देंगे। एलाइट पुरुष और महिला विजेताओं में से प्रत्येक को 45,000 अमेरिकी डालर का पुरस्करण मिलेगा। इसके अलावा धावकों को कोर्स रिकार्ड बोनस के तौर पर 15,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। साल 2021 में आयोजित गुआडलाजरा मैराथन को 2:12:28 घंटे समय में जीतने वाले हुरिसा ने कहा, मैं चुनौती के लिए तैयार हूं और मेरी नजर

खिलाफ पर है। पुरुष वर्ग में हुरिसा के अलावा उनके हमरवन आइले एम-प्रायर धावक भी मुंबई की साथ-साथ केन्द्र के फिलेमोन रोनो भी हैं, जो दिग्गज प्रायर युड किप्पोरों के साथ अभ्यास करते हैं। एथ्सेरो 2020 में एआईएमएस-प्रमाणित क्षेत्र पर हुरिसा से 11 सेकंड पीछे रहे हाल उत्तिजित रहे। इसके अलावा धावकों को कोर्स रिकार्ड प्रायर को काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आस्ट्रिया में 2022 तिंज मैराथन में 2:09:37 घंटे समय के साथ 10वां स्थान हासिल करने वाले एथ्सेरो का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 2:04:23 घंटा है, जो उन्हें फील्ड में सबसे तेज धावक बनाता है। उन्होंने 2021 अबू धाबी मैराथन और 2022 सोल

के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ, लेमी इस समूह में दूसरे सर्वश्रेष्ठ देने वाले धावक हैं। 2016 में दुबई मैराथन और 2015 में दुबई मैराथन सहित सात मैराथन के विजेता लेमी ने कहा, मैं टाटा मुंबई मैराथन में डेव्यू को लेकर उत्साहित हूं। मैं सुना है कि यह एक कठिन कोर्स है। लेमी साल 2021 में आयोजित बोर्डर मैराथन के उत्तिजित रहे थे। रोनो ने 2019 बोर्डर मैराथन में प्रावासाली रूप से छठा स्थान हासिल किया और उसी वर्ष 2:05:00 घंटे में ट्रोटो मैराथन जीता था। उन्होंने 2021 अबू धाबी मैराथन और 2022 सोल

## देशन का फिट चयन समिति का प्रमुख बनना तय

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्म एक बार फिर इसी पद को संभाल सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चेतन को फिर से अध्यक्ष बनाना चाही है। इससे पहले बीसीसीआई ने टी20 विश्वकप में टीम की हार के बाद चेतन की अध्यक्षता वाली समिति को बद्वास्त कर दिया था। उसके बाद बोर्ड ने चयन समिति के लिए आवेदन मारे थे। उसी को देखते हुए चेतन ने भी आवेदन किया था। श्रीलंका के खिलाफ टीम चयन भी उन्हीं की अध्यक्षता में अतिरिक्त समिति ने किया है। अब माना जा रहा है कि वे ही चयन समिति उन्होंने अपने करियर में 23 टेस्ट और 65 एकदिवसीय मैच खेले। टेस्ट में 61 और एकदिवसीय प्राप्त में 433 विकेट दर्ज हैं। क्रिकेट से सन्यास के बाद वह केमेट्रर भी रहे। उनके नाम आईसीसी विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले मेंदवाज बनने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने यह उपलब्धि 31 अप्रैल 1987 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नामांगुले हैं।

खेल

क्रांति समाय









# अंतरराज्यीय क्रूड ऑयल माफिया संदीप गुसा कोलकाता से गिरफ्तार

**क्रांति समय, सूरत**

[www.krantisamay.com](http://www.krantisamay.com)

[www.paper.krantisamay.com](http://www.paper.krantisamay.com)

सूरत, गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में गुजरने वाली भूमिगत पाइप लाइनों में छेद कर क्रूड ऑयल चोरी करने वाले वांछित माफिया संदीप को गुसा को सूरत क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

शहर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि संदीप गुसा उर्फ़ सेंडी हरियाणा के गुरुग्राम का मूल निवासी है। वह 2006 से ही विभिन्न राज्यों में ऑयल चोरी में सक्रिय है। वह अलग अलग राज्यों में अपने साथियों के साथ मिल



कर ऑयल चुराता था। फिर अपने नेटवर्क के जरिए अन्य माफियाओं के साथ मिली भगत कर चोरी छिपे बेचता था। उसके खिलाफ करीब 400 करोड़ रुपये की ऑयल चोरी के मामले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व पश्चिम बंगाल के

## ज्वेलर्स की दुकान से ग्राहक के भेष में ठग महिला ने 75 हजार के कंगन पर हाथ साफ किया

**क्रांति समय, सूरत**

[www.krantisamay.com](http://www.krantisamay.com)

[www.paper.krantisamay.com](http://www.paper.krantisamay.com)

शहर के घोड़दौड़ रोड कैनोपस मॉल में शाह जयंतीलाल सन्स एंड ज्वेलर्स नाम की एक ज्वैलरी दुकान है।

दुकान में ग्राहक के रूप में आयी एक ठग महिला ने सेल्सगर्ल की नज़र चुराकर 75 हजार रुपये के कंगन चुरा लिये। उमरा पुलिस ने 14 ग्राम सोने के 75 हजार के कंगन चुरा कर भागी महिला की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है।

**ठग महिला की चोरी की हक्कत सीसीटीवी में कैद**



एक दुकान में रोजाना की तरह रात 8 बजे पूरे दिन का अकाउंट चेक कर रहे थे।

इस बीच सोने की मशीन के डिजाइन वाला एक कंगन गायब मिला और दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।

जिसमें दोपहर करीब 1 बजे ग्राहक के बेश में सफेद पोशाक व लाल दुपट्टा पहने एक ठग महिला ने जेवर

माल, घोड़दौड़ रोड (उम्र 36 निवासी सहयोग एपार्टमेंट, विद्याकुंज स्कूल के पास, पालनपुर जकातनाका) की

उसे पकड़ा गया था। उस दौरान उसके ब उसके साथियों के खिलाफ गुजरीटोक (गुजरात संगठित अपराध व आतंकवाद निरोधक कानून) के तहत मामला दर्ज किया गया था। छह माह पूर्व वह कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर फरार हो गया था।

तब उसे पुलिस को उसकी तलाश थी, इस बीच सूरत क्राइम ब्रांच को उसके कोलकाता में छिपे होने की खबर मिलने पर पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वह फिर से राजस्थान में अपने ऑयल चोरी के नेटवर्क को बेचता था।

उसकी सक्रिय करने के फिराक में

था।

ऐसे करता था चोरी माफिया संदीप पहले भूमिगत ऑयल पाइप लाइन का पता लगाता था। फिर वहां ऑयल चोरी का अपना पूरा नेटवर्क बनाता था। उसके पाइप लाइन के एक किलोमीटर के दायरे में बंद फैक्ट्री या शेड़ किए गए पर लेता था। पाइप लाइन छेद करवा कर वहां से गुप्त पाइप लाइन के जरिए ऑयल को अपने शेड़ में गुप्त रूप से यह खुलासा हुआ है।

वह घर में ही गांजे के पैकेट बनाता था एसओजी को मिली सूचना के आधार पर एसओजी ने लिंबायत बेठी कॉलोनी में

गुजरात/सूरत

क्रांति समय

आठ किलो गांजे के साथ पकड़ा गया युवक, एक किलो कीमत 24 हजार रुपये होने का खुलासा

**क्रांति समय, सूरत**

[www.krantisamay.com](http://www.krantisamay.com)

[www.paper.krantisamay.com](http://www.paper.krantisamay.com)

सूरत पुलिस के नो-ड्रॉप अभियान के बाद शहर में गांजे को तस्करी करना मुश्किल हो गया है। सूरत में गांजे की कमी को महसूस करते हुए एक किलो गांजे के दाम बढ़ा दिए हैं। ओडिशा से 5 हजार रुपये में एक किलो मिलने वाले गांजे की कीमत अब 24 हजार रुपये प्रति किलो कर दी गई है। लिंबायत से 8 किलो गांजा के साथ पकड़े गए युवक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है।

मामा ने गांजा लाकर दे दिया वसीम से पूछताछ करने पर पता चला कि वह गांजे की पालिका ने चुकाई और बड़ी मुश्किल से उड़ीसा से गांजा लाए और उसे बेचता है। उसे गांजे का जट्था अपने मामा अकरम अलारखा शेख (निवासी भौठीखड़ी, लिंबायत) और उनके दोस्त सोएब इकबाल शेख (निवासी लिंबायत बेठी कॉलोनी में

## अब शहर में घरेलू कचरा उठाने आएंगे ई-वाहन

**क्रांति समय, सूरत**

[www.krantisamay.com](http://www.krantisamay.com)

[www.paper.krantisamay.com](http://www.paper.krantisamay.com)

हाल ही में ध्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 ई-चार्जिंग स्टेशनों को लॉन्च करते हुए शहर को ई-शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। नगर पालिका ने भी घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों को प्रशासनिक उड़ानों से इ-वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत 1 जनवरी से कचरा संग्रहण के लिए 124 ई-ट्रेम्पो लॉन्च किए गए थे।

कुछ जोन में ट्रैक्टर से कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा था। अब ट्रैक्टर के स्थान पर 24 ई-ट्रेम्पो लॉन्च किए गए थे।

कहा कि झारखंड सरकार के फैसले ने सूचूचे जैन समाज मौरैली निकाली। जिसमें जैन संप्रदाय के संत महामुनि और श्रावकों समेत 15000 से भी अधिक लोग बैनर-पोस्टर लेकर शामिल हुए।

जैन समाज के लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार के फैसले ने सूचूचे जैन समाज मौरैली निकाली। जिसमें जैन संप्रदाय के संत महामुनि और श्रावकों समेत 15000 से भी अधिक लोग बैनर-पोस्टर लेकर शामिल हुए।

जैन समाज के लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार के फैसले ने सूचूचे जैन समाज की आस्था को चोट पहुंचाई है।

सकल जैन समाज सूरत को मुख्य उद्देश्य केवल एक ही मांग है कि उनके पवित्र तीर्थ के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। झारखंड सरकार द्वारा संप्रदाय के पर्यटन स्थल की घोषणा वापस ली जाए और पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए।



लिए सड़कों पर उतरेंगे। नगर पालिका का कहना है कि शेष वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत 1 जनवरी से ई-वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सोसायटियों को कूड़ा निस्तारण के लिए राजी किया जाएगा।

मनपा आयुक्त ने गर्वेज सेग्रेगेशन की समीक्षा की

प्रश्नाएं जैसे ग्रामीण जीवन का अवधारणा का अधिक सोसायटीयों में अगले तीन माह में धीरे-धीरे समझाइश दी जाएगी।

मनपा आयुक्त ने गर्वेज सेग्रेगेशन की समीक्षा की अधिक शालिनी अग्रवाल ने सुविधा रो हाउस सोसायटी में सेग्रेगेशन की समीक्षा की और निरीक्षण किया कि कचरा संग्रहण वाहन द्वारा सोसायटी से सूखा और गीले कचरे को अलग किया जा सके।

9 जून में 100-100 एनजीओ के माध्यम से 900 सोसायटियों के अध्यक्षों से मिले और सुखे-गीले कचरे के पृथक्करण के बारे में जागरूक कर दिया गया। एनजीओ के माध्यम से 124 ई-वाहन लॉन्च किए गए थे।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

आयुक्त ने सोसायटी के अध्यक्ष के साथ ही अपने लॉन्चर के साथ वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

</div